सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-14 | 22 जुलाई से 5 अगस्त, 2017 | मुख्य संपादक : कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

विश्व सर्वहारा के महान नेता

5 दिसम्बर 1820 - 5 अगस्त 1895

फ्रेडरिक एंगेल्स

लाल सलाम

''पूंजीपति अब अपने मजदूर को काम पर लगाता है। कुछ समयावधि में ही मजदूर उतना श्रम कर चुका होगा जितनी उसकी हफ्ते की मजदूरी बनती है। मान लीजिए एक मजदूर की हफ्ते की मजदूरी तीन दिन का प्रतिनिधित्व करती है, तब अगर मजदूर सोमवार से काम शुरू करे, तो वह बृहस्पतिवार शाम तक वह उसे दी गई मजदूरी की पूरी कीमत पूंजीपति को बदले में दे चुका होता है। लेकिन क्या वह फिर काम करना बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं। पूंजीपति ने उसका एक हफ्ते का श्रम खरीदा हुआ है और मजदूर को हफ्ते के बाकी आखरी तीन दिन भी काम करते जाना होगा। मजदूर का यह सरप्लस (अतिरिक्त) श्रम, सर्वोपरि उसकी मजदूरी को प्रतिस्थापित करने के लिए जरूरी श्रमकाल ही सरप्लस वैल्यू (अतिरिक्त मूल्य), मुनाफे, लगातार बढ़ती पूंजी का स्रोत है। ... सरप्लस मूल्य का उद्गम (जिसका एक महत्वपूर्ण भाग पूंजीपतियों का मुनाफा बनता है) अब साफ जाहिर है और स्वाभाविक है। श्रमशक्ति का मूल्य दे दिया जाता है, लेकिन यह मूल्य उतने से बहुत ही कम होता है जितना पूंजीपति इस श्रमशक्ति से निचोड़ने का प्रबन्ध कर लेता है, और ठीक यही अन्तर वह श्रम होता है जिसका भुगतान नहीं किया गया है, जो पूंजीपतियों, या ज्यादा सही - सही कहें तो पूंजीपति वर्ग के हिस्से में इजाफा करता है।''

(डेमोक्रेटिचेस वोचेनब्लाट के लिए पूंजी के प्रथम खण्ड की समीक्षा, मार्च 1868)

मिट्टी तेल व चीनी पर से सब्सिडी समाप्ति का एसयूसीआई(सी) ने किया का विरोध

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 15 जुलाई को जारी एक बयान में कहा :

नितांत जनविरोधी नीतियों को निरंतर आगे बढ़ाने के अपने प्रयास में बीजेपी-नीत केन्द्र सरकार ने अंत्योदय योजना के अलावा विभिन्न स्कीमों के तहत बीपीएल श्रेणी के लोगों को मिलने वाले मिट्टी तेल के कोटे में कटौती और सब्सिडी खत्म करने के बाद अब चीनी के कोटे के बारे में इसी तरह की कटौती और सब्सिडी समाप्ति की घोषणा की है। इसके परिणाम स्वरूप इन दो जरूरी चीजों के दामों में भारी इजाफा होगा जिसके चलते मेहनतकश जनता के गरीब तबके पर भारी चोट पड़ेगी। एक तरफ, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की रोजाना बढ़ती महंगाई ने मेहनतकश जनता का खून पहले ही पूरी तरह निचोड़ लिया है। दूसरी तरफ, यही केन्द्र सरकार बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों, बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों और बड़े-बड़े इजारेदार पूंजीपतियों को दरियादिली के साथ टैक्स माफी, टैक्सों में छूट, वित्तीय सहायता और बेल आऊट पैकेज देने के साथ-साथ उनकी कर्ज देनदारियां भी माफ कर रही है। इसने एक बार फिर पर्दाफाश कर दिया है कि किस तरह बीजेपी सरकार मेहनतकश जनता के खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ कर नग्न रूप से शासक पूंजीपति वर्ग की सेवा कर रही है।

केन्द्र सरकार की इस नितांत गरीब-विरोधी नीति की हम कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि चीनी व मिट्टी तेल, दोनों के मामले में सब्सिडी समाप्ति और कोटे में कटौती के इन फैसलों को तुरंत वापस लिया जाये।

सर्वहारा के महान नेता, इस युग के अग्रणी मार्क्सवादी चिंतनकार

कॉमरेड शिवदास घोष की 41वीं मृत्यु वार्षिकी सम्मानपूर्वक मनायें

सर्वहारा के महान नेता, एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव, हमारे शिक्षक, पथ प्रदर्शक और इस युग के अग्रणी मार्क्सवादी चिन्तनकारों में से एक कॉमरेड शिवदास घोष की 5 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। इस साल उनकी 41वीं बरसी है। 1976 में इस दिन मेहनतकश जनता ने अपना क्रान्तिकारी नेता खो दिया था। इस महान मार्क्सवादी अथोरिटी के गुजर जाने से हमारे पार्टी जीवन में गम का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन महान लेनिन से सीख लेकर तभी से हम अपने इस दुख को दृढ़ सकल्प में बदलने में लगे हुए हैं। देश के मेहनतकशों के लिए जहां यह दिन बहुत ही शोक का दिन है वहीं उनके दिखाये रास्ते पर चलने के लिए अपने आपको और भी तैयार करने की शपथ लेने का भी दिन है। मेहनतकश जनता को कॉमरेड शिवदास घोष ने इस पूंजीवादी शोषण से मुक्ति की राह दिखायी थी। उन्होंने मुक्ति-संघर्ष के औजार के तौर पर सर्वहारा वर्ग की सही क्रान्तिकारी पार्टी, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) का गठन किया था। भारत की सरजमीन पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद के ज्ञान-भण्डार को भी उन्नत, विकसित व समृद्ध किया था। पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रन्ति के उनके दिखाये रास्ते पर चल कर उनके अधूरे सपने को साकार करने के लिए हम उनके विचारों को गहराई से जानने-समझने और उनके विचारों को क्रान्तिकारी कार्रवाईयों और गतिविधियों में रूपान्तरित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। दरअसल इसी में हमारा अस्तित्व निहित है। इसी क्रम में, हर साल की तरह इस साल भी हम 5 अगस्त को उनकी सीखों के आधार पर देश के क्रान्तिकारी आन्दोलन की तीव्र विकास-वृद्धि के लिए खुद को एक बार फिर समर्पित कर देने की शपथ लेने के दिन के तौर पर मना रहे हैं। एक फौलादी क्रान्तिकारी के तौर पर खुद को ढालने का संकल्प हम एक बार फिर दोहराते हैं। कामरेड शिवदास घोष की सीखों के अनुसार ही 5 अगस्त का

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कृषि कर्ज माफी

किसान आन्दोलन में आई लहर तेज करें और इसे अंतिम लक्ष्य की परिणति तक पहुँचायें

किसान आन्दोलन की एक नई लहर जबरन भूमि अधिग्रहण व बेदखली के खिलाफ नन्दीग्राम-सिंगुर के किसानों द्वारा चलाये गये शानदार संघर्ष से शुरू हुई। अभी महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडू, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक के पीड़ित गरीब किसान कर्जमाफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई सुविधा, बिजली व डीजल के दामों में रियायत आदि कुछ जायज मांगों के सवाल पर सरकार के साथ संघर्षरत हैं। बीजेपी-नीत सरकार जो अपनी पूर्ववर्ती सरकार के सारे हथकण्डों में पारंगत है, शोषित जनता के ऊपर भारी आर्थिक बोझ डालने के साथ-साथ झूठे वायदे कर रही है। लम्बे समय से किसानों की मांगों के प्रति आपराधिक निष्क्रियता बनाई हुई है। उनमें उपजे असंतोष का किसी भी प्रकार का संज्ञान न लेने का बहाना ढूढ़ रही है। अब जब संचित रोष एवं शिकायतें स्वत:स्फूर्त जन-आन्दोलन व प्रदर्शन में फूट पड़े हैं तब इसने अपने फासीवादी चरित्र का नग्न चेहरा दिखा दिया। मंदसौर में छह जून को किसान आन्दोलन के दौरान पुलिस ने गोलीबारी की जिसमें आधा दर्जन किसान मारे गए तथा बहुत सारे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसने आग में घी का काम किया। आन्दोलन और उग्र हो गए तथा दूसरे प्रदेशों में भी फैल गए जिसके बाद सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर होना पड़ा। आन्दोलन के दबाव में बी.जे.पी. नेतृत्व वाली सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी की घोषणा कर डाली। यद्यपि इसमें कुछ कठोर शर्तें भी शामिल हैं। इनसे जरूरतमंदों अर्थात् सीमांत व गरीब किसानों के हाथों फायदा पहुँचने पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। किन्तु इस घोषणा के कुछ ही समय के अन्दर सरकारी विभागों में पदेन अधिकारियों के साथ-साथ अर्थशास्त्री, समीक्षक, समालोचक, बैंकर्स, नौकरशाह आदि समस्त शासक पूँजीपति सेवादारों ने विलाप करना शुरू कर दिया कि किसानों को भारी-भरकम रियायतें देना देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बुरा है, कैसे यह क्रेडिट अनुशासन जिसका मतलब कर्ज का उपयुक्त वितरण व वसूली है, को जोखिम में डाल देगा, ऋण वसूली नीति को स्थायी बट्टा लग जाएगा, इससे बीजेपी-नीत केन्द्र सरकार के हाल के मितव्ययता अभियान को धक्का लगेगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर को कम करने की स्थिति को सीमित कर देगा इत्यादि। सरकार द्वारा इस प्रकार की अपव्ययता व फिजूलखर्ची का आर्थिक परिणाम कैसे प्रभावित होगा। चर्चा यहीं तक सीमित नहीं थी बल्कि शासक गलियारों ने यह भी आरोप लगाया कि किसान जानबूझकर कर्जा नहीं चुकाते ताकि कर्ज माफ हो जाए। कुछ 'समझदार' लोगों ने धृष्टतापूर्वक किसानों को आरोपित किया कि वे कर्ज राशि को ऐशो-आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं तथा फैशन के लिए कर्ज माफी की मांग करते हैं। किन्तु वे बैंकों द्वारा बड़े उद्योगपतियों, बड़े कृषि व्यापारियों तथा बड़े भू-स्वामियों को दिये गये कर्ज के बकाए को खुले तौर पर माफ करने में कोई गलती नहीं देखते हैं। न ही वे कोई पक्षपात देख पाते हैं कि कैसे जब किसान कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाते हैं, तब उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मारा-पीटा जाता

(शेष पृष्ठ 2 पर)

5 अगस्त ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

यह भी आह्वान है कि समाज, क्रान्ति और क्रान्तिकारी पार्टी के साथ हम खुद को पूरी तरह से एकाकार करने के अपने संकल्प को एक बार फिर दोहरायें।

इस साल यह दिन ऐसे समय आ रहा है जब बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शोषण, दमन-उत्पीड़न, टैक्सों की मार, बढ़ते कर्ज-जाल में फंसे किसानों की दर्दनाक आत्महत्याओं का सिलसिला, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, शिक्षा-संस्कृति पर हमले, अश्लीलता, नशोखोरी व अपराध से हमारे देश में माहौल दमघोंटू होता जा रहा है। घोर साम्प्रदायिक कट्टरपंथी ताकत आरएसएस-बीजेपी और उसकी अन्य शाखायें अपने आकाओं, सरमायेदारों के इशारे पर संसदीय लोकतंत्र के मुखोटे की आड़ में प्रशासनिक फासीवाद लाने की प्रक्रिया को और भी तेज करने पर तुली हुई हैं। यह मरणासन्न पूंजीवाद देश में फासीवाद कायम करने की अपनी योजनाओं और रूपरेखाओं के साथ अब अपने सभी पंजे और दांत और भी आक्रामकता के साथ और खूँख्वार रूप में प्रकट कर रहा है। सरकार के कार्यकलापों और नीतिगत घोषणाओं से और भी फासीवादी रुझानों की बू आ रही है जो लोगों के लिए गंभीर खतरे का पूर्वाभास देते हैं। मेहनतकश जनता में फूट के जहरीले बीज बोये जा रहे हैं। इस प्रकार साम्प्रदायिक और जातिवादी ताकतें ऐसे हालात पैदा कर रही हैं जिनमें एकताबद्ध जनवादी आन्दोलन गठित करना सचमुच में बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मौजूदा संविधान में जो भी अधिकार प्रतिष्ठापित हैं उन सर्वजनीन मानव अधिकारों, मौलिक अधिकारों को भी ये गहरी चाल चल कर पैरों तले रौंद रही हैं। पूँजीपति वर्ग के पृष्ठपोषण से उनकी अगुवाई में आज एक फासीवादी हुकूमत कायम होने का वास्तव में खतरा है। जाहिर है कि आज जो कुछ भी जनतान्त्रिक ढांचा बचा-खुचा है, उसे भी ये जोखिम में डाल रही हैं। साथ ही साथ मुस्लिम-विरोधी हर तरह के दुष्प्रचार को आये दिन उकसा रही हैं जिससे साम्प्रदायिक द्वेष फैलता दिखाई दे रहा है। इससे भी ज्यादा चिन्ताजनक बात यह है कि अन्य सभी राजनैतिक पार्टियां इस घोर साम्प्रदायिक ताकत के खिलाफ किसी तरह का प्रतिवाद खड़ा करने के मूड में नहीं हैं, उल्टे उन्होंने साफ तौर पर किसी भी तरह के टकराव से बचने का रास्ता चुन लिया है। कॉमरेड शिवदास घोष ने बार-बार दिखाया था कि फासीवाद इन्सान बनने की प्रक्रिया को ही खत्म कर देता है। यह इन्सान को हैवान बना देता है। मानवीय मूल्यों, नीति-नैतिकता और संस्कृति से विहीन कर आदमी को एक यन्त्र सा बना देता है। अगर फासीवाद देश में निर्णायक हद तक जड़ जमा लेता है तो समाज में प्रतिवाद की आवाज और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की इच्छा का ही लोप हो जायेगा। फासीवाद सभी पूंजीवादी देशों में, चाहे विकसित हों या पिछड़े, एक आम लक्षण बन चुका है। फर्क केवल उसके रूप और मात्रा में है। भारत में फासीवाद की नींव राष्ट्रीय बुर्जुआ पार्टी, कांग्रेस ने पहले ही रख दी थी। अब बीजेपी-आरएसएस सत्ता में आने के बाद हिन्दू धार्मिक कट्टरतावाद, मध्ययुगीनता और परम्परावाद को और भी उकसा कर, मिथकों को इतिहास के रूप में फैला कर और मनघड़न्त विचारों, हवाई बातों व दंतकथाओं को विज्ञान के रूप में फैला कर फासीवाद को और भी मजबूत कर रहे हैं। उनका मकसद है लोगों के वैज्ञानिक और तार्किक रुझान वाले मन को नष्ट कर देना और उसकी जगह उनमें अंधविश्वास भर देना। साफ जाहिर है कि ये हालात हमारी पार्टी से एक जबरदस्त भूमिका निभाने की मांग कर रहे हैं।

साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय हालात भी आज वास्तव में गम्भीर हैं। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में तमाम साम्राज्यवादी ताकतें बेलगाम हो गई हैं और दुनिया के तमाम लोगों को बन्धक बनाये हुए हैं। इनके द्वारा विभिन्न देशों में खुल्लम-खुल्ला फौजी दखलन्दाजी करना और जब चाहा विभिन्न देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देना आज आम बात हो गई है। लेकिन घुप अंधेरे में भी आशा की रूपहली किरण साफ नजर आ रही है। ये सभी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी आज जोरदार जन प्रतिवाद से रूबरू हैं। खुद उनके ही देशों में जनाक्रोश का लावा फूट पड़ रहा है। इन जन आन्दोलनों को नाकाम कर देने के लिए वे दमन और छल-फरेब का सहारा ले रहे हैं।

मौजूदा हालात मांग करते हैं कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतन से लैस एक जांबाज नेतृत्व उभर कर आना चाहिए। कॉ. शिवदास घोष की अमूल्य सीखों से लैस होकर हम तमाम बुर्जुआ बुराइयों का मुकाबला करते हुए अपना सैद्धान्तिक, राजनैतिक, सांगठनिक, नैतिक-सांस्कृतिक स्तर व पहलकदमी बढ़ायें। वर्ग, क्रान्ति व पार्टी हित के साथ अपने निजी स्वार्थ को एकात्म कर देने के संघर्ष में हम जोरशोर से लग जायें ताकि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतनधारा और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के परचम को हम कामयाबी के साथ बुलंद कर सकें। कॉमरेड शिवदास घोष के जीवन-संघर्ष से हमें सीख लेनी है। उनके विचारों को जन-जन तक ले जाना है। जहां भी कॉमरेड शिवदास घोष का विचार पहुंच रहा है, वहीं लोग संगठित होते जा रहे हैं और शोषण-जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज पार्टी को जबरदस्त जन-समर्थन मिल रहा है। ईमानदार लोग आगे आ रहे हैं। पार्टी बढ़ने के साथ-साथ वर्ग संघर्ष व जनआन्दोलन भी बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति की जमीन तैयार कर रहे हैं।

ऐसे दमघोंटू राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय हालात की पृष्ठभूमि में हम 5 अगस्त मनाने जा रहे हैं। इस साल महान नवम्बर क्रान्ति का शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस संदर्भ में 5 अगस्त मनाने का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन को हमें सर्वहारा वर्ग की सही क्रान्तिकारी पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) को मजबूत करने और इसे साधन-सम्पन्न बनाने के ख्याल से मनाना चाहिए। यह दिन हमारे पूरे पार्टी जीवन में सबसे ज्यादा दुखद दिन होने से, इस दिन हम सब नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, हमदर्द एक साथ मिल कर उनके क्रान्तिकारी चिन्तन, लक्ष्य और आदेशों के प्रति अपने आपको पुनःसमर्पित करने, उनके उदाहरणीय जीवन-संघर्ष से सीख लेने, उनके द्वारा पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई उसकी प्रक्रिया को तेज करने, उसके परिपूरक वर्ग संघर्ष और जनसंघर्षों को जारी रखने की शपथ लेते हैं। सर्वहारा वर्ग, समाज, क्रान्ति और पार्टी के हित के साथ अपने हित को एकाकार करने और खुद को समर्पित और पुनःसमर्पित करने के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे।

कृषि कर्ज माफी...

(पृष्ठ 1 का शेष)

है। उनकी जमीन को कुर्क या निलाम कर दिया जाता है या फसल को जब्त कर लिया जाता है। जबकि बड़े कर्जदारों का कर्ज माफ कर दिया जाता है या उन्हें नया कर्ज दे दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे अपना समस्त आर्थिक दायित्व किसानों के मत्थे जड़ देना चाहते हैं।

किसानों का तबाह होता जीवन

ग्रामीण भारत का परिदृश्य क्या है? क्या यह दो तिहाई भारतीय जो वहाँ बसते हैं उनके लिए चित्ताकर्षक है? या फिर उनका जीवन दुख व तकलीफ से ग्रसित है? टीकाकारों के अनुसार कृषि क्षेत्रों में संख्या व क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत दुनिया के पहले पाँच देशों में शुमार है। किन्तु जब 95% ग्रामीण जनसंख्या में किसानों की स्थिति की बात होगी तो दृश्य त्रासदीपूर्ण हो जाता है। खेती का घटता रकबा, भूमिगत जल स्तर का नीचे गिरते जाना, सिंचाई व्यवस्था नदारद, मिट्टी की गुणवत्ता का क्षरण, बढ़ता लागत खर्च, उपज के घटते दाम, कम उपज, कमजोर मानसून, सूखा व बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं, भ्रष्ट सरकारी खरीदतंत्र, उपज को मजबूरन बेचने की विवशता, कर्जों में इजाफा, खुदकुशी की बढ़ती जा रही घटनाएं–यह सब किसानों के जीवन को तबाह कर रही हैं। गरीबी और बेबसी का मारा किसान अपनी जमीन तक बचा नहीं पा रहा है। आर्थिक विपन्नता के हालात से किसी तरह उबरने के लिए वे या तो अपनी जमीन बेच रहे हैं या फिर बंधक रख रहे हैं। इस तरह वे अपनी जमीन खो रहे हैं। अपनी जमीन को खोकर एक तरफ मध्यम वर्गीय किसान सीमांत किसान में, सीमांत किसान बंटाईदार किसान में, बंटाईदार किसान भूमिहीन किसान में या खेतिहर मजदूरों में तब्दील होता जा रहा है। वहीं सारी जमीन भू-माफियाओं या ग्रामीण अमीरों के पास संचित होती जा रही है। यहाँ तक कि खेतीहर मजदूर खेती-बाड़ी का काम न रहने के चलते किसी भी तरह की मजदूरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। खासकर पूँजीवादी भूमण्डलीकरण के आर्थिक सुधार में हुई बदहाली ने उसे और भी दयनीय बना दिया है। एक अच्छी संख्या में भारतीय किसान कम उपज से परेशान हैं। उपज और आय में भारी कमी आई है। फसल कटाई के बाद उपयुक्त भण्डारण सुविधा काफी कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति में बढ़ रही गरीबी-दरिद्रता दुगुनी हो गई है। इस तरह वे सब कुछ खोकर एक स्थान से दूसरे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काम की तलाश में निर्वासित मजदूर बन गए हैं तथा बेबस दयनीय जीवन को संभालने की कोशिश करते हैं। लगभग आधी ग्रामीण आबादी भूमिहीन है। ये पचास प्रतिशत भूमिहीन आबादी अपनी आय के बहुत बड़े भाग के लिए कैजुअल-मैनुअल श्रम पर आश्रित हैं जिसे कोई श्रमिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। कोई नौकरी-सुरक्षा नहीं है। कोई कमाई की सुरक्षा नहीं है। वे अत्यंत दमघोंटू, कठोर परिश्रम से भरा दुष्कर काम करने के लिए बाध्य हैं। कई बार सरकार द्वारा बहुफसली जमीन के बड़े-बड़े भूखण्ड प्राइवेट पूंजी निवेशकों के व्यावसायिक हित में, उनके हवाले कर दिये जाने से वे जबरन घर-बार से बेदखल कर दिए जाते हैं। ठोकर खाने को मजबूर ये किसान धीरे-धीरे फटेहाल, कंगाल, भुखमरी के शिकार होकर फुटपाथ को रैन बसेरा बना लेते हैं तथा सड़क किनारे कुत्ते-बिल्लियों की तरह अज्ञात मर जाते हैं। सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों से पता चलता है कि अनुमानतः हर दिन 2035 किसान खेती-किसानी का काम छोड़ देते हैं। पचास प्रतिशत ग्रामीण परिवार कैजुअल मैनुअल श्रम पर आश्रित हैं। 6.68 लाख परिवार भीख मांगकर गुजारा करते हैं जबकि 4.08 लाख परिवार कचरा-कबाड़ बीन कर अपनी जीविका चलाते हैं। 40 प्रतिशत किसान जीने का दूसरा विकल्प मिल जाने पर खेती-बाड़ी छोड़ देना चाहते हैं। भारत एक विशाल कुपोषित व भुखमरी की शिकार आबादी का बसेरा है। 195 मिलियन लोग रोजाना भूखे सोने पर मजबूर हैं। उसमें ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण गरीब व बेबस किसानों का है। यह दीन-हीन, विवश, कृश्यकाय किसानों की अर्ध-सर्वहारा से सर्वहारा में परिवर्तन की तस्वीर है। उसमें अच्छी-खासी संख्या अत्यंत कठोर कदम खुदकुशी का लेते हैं। जो उनके बेबसीभरे व निरर्थक जीवन की कहानी बयां करती है। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति जिनके पास पीड़ित मानवता के लिए न्यूनतम मानवीय संवेदनाएं एवं सरोकार हैं वे भारतीय किसानों की विवशता, नारकीय जीवन को देख कर अपने आँसू नहीं रोक पाएंगे।

कर्ज के जाल में कैसे फंस जाते हैं किसान?

यह स्पष्ट है कि यदि केन्द्र व सूबे की बुर्जुआ सरकार किसानों को देश की रीढ़ बता कर आसमान में बिठा कर सत्ता के गलियारों में खेल खेलने की जगह उनके भविष्य सुधारने की थोड़ी सी भी सावधानियाँ बरती होतीं तो आजादी के बाद अन्नदाताओं की स्थिति इस कद्र शर्मसार करने वाली नहीं होती। सरकार, सत्तासीन दल, उनके विद्वान आर्थिक सलाहकार एवं पण्डिताऊ कृषि विशेषज्ञ मुखवाणी यानी जबानी जमाखर्च के सिवा और कुछ नहीं करते। वे गरीब किसानों के गिरते हुए जीवन स्तर के लिए किसी प्रकार का सरोकार महसूस नहीं करते हैं। ये बुर्जुआ सरकारें लोगों के लिए बहुत कुछ करने का ढोंग करती हैं किन्तु वास्तव में

(शेष पृष्ठ 4 पर)

एसयूसीआई(सी) ने जनसभा में दी मंदसौर में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि

अशोकनगर (म.प्र.) : विगत 6 जून को म.प्र. के मंदसौर जिले में अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई जिसमें 6 किसानों की जान चली गई व कई किसान घायल हो गये। उक्त घटना के एक महीना पूरा होने पर 6 जुलाई को एसयूसीआई(सी) व किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के नेतृत्व में स्थानीय पछाडीखेड़ा चौराहा विमानों के चबूतरे पर श्रद्धांजली सभा आयोजित की गई।

ज्ञात हो 14 जून 2017 को एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी के आह्वान पर मंदसौर में शहीद हुए किसानों को श्रद्धाजंली देने के लिए अपील की गई थी उसी आह्वान पर अशोकनगर मंदसौर जिले के शहीद किसानों को श्रद्धांजली देने के लिए शहीद वेदी बनाई गई। शुरू होने से पहले ही पुलिस-प्रशासन द्वारा शहीद वेदी व पूरा सामान छीन लिया गया था और उपस्थित साथियों को पुलिस वेन में बिठाकर पुलिस थाने ले गई। सभी ने सोचा कि कुछ कागजी कार्यवाही करके 2-3 घंटे बाद सभी को छोड़ देंगे लेकिन थाने में तीन घंटे तक पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड सचिन जैन, केकेएमएस के मोहनसिंह यादव सहित 20 कार्यकर्ताओं को अंदर रखा गया। तहसीलदार ने जानबूझकर जमानत नहीं दी। चार महिला कार्यकर्ताओं को मुचलके पर छोड़ दिया गया और 16 पुरुष कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। अगले दिन भी तहसीलदार जानबूझकर छुट्टी पर रहने की वजह से उस दिन भी जमानत नहीं हुई। बमुश्किल तीसरे दिन जमानत दी गई। शहर के वामपंथी, बुद्धिजीवी व जनवाद पसंद लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। जेल से बाहर निकलने पर सभी साथियों का शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा फूलमालाएं पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जेल से निकले सभी कार्यकर्ताओं ने जनआंदोलन को और तेज करने का दृढ़ संकल्प लिया।

इस घटना के प्रतिवाद के रूप में 6 जुलाई को बड़े स्तर पर एसयूसीआई(सी) जिला कमेटी द्वारा श्रद्धांजली सभा करने का फैसला लिया गया। शहर व आसपास के लगभग 40 से अधिक गावों में प्रचार व तैयारियां की गई। सभा में लगभग 1000 छात्र-नौजवानों, किसानों, महिलाओं ने हिस्सा लिया और इस आंदोलन को समर्थन दिया। सभा की शुरूआत जनगीतों से की गई। एसयूसीआई(सी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य व किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉ. सत्यवान सभा के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने कहा कि मंदसौर में आन्दोलनकारी किसानों पर गोली चलाना सरकार का घोर आलोकतांत्रिक कदम है। पुलिस-प्रशासन द्वारा 6 किसानों की हत्या कर दी गई है। किसान प्राकृतिक आपदा में फसल की बर्बादी झेलता है। बंपर उत्पादन होने पर किसान फसल के वाजिब दाम न मिलने के कारण अपनी उपज को सड़कों पर फेंकने को भी विवश हैं। ऐसी स्थिति में किसान कर्ज में डूबकर आत्म-हत्याएं कर रहे हैं जबकि सरकार बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों को खेती में मुनाफा कमाने की खुली छूट दे रही है। चंद पूंजीपति घरानों को लगभग 11लाख करोड़ रुपये का कर्ज सरकार बट्टे खाते में डाल कर माफ कर देती है जबकि कर्ज न चुका पाने की दशा में बैंक द्वारा किसानों की सम्पत्ति, जमीन-जायदाद जब्त कर ली जाती है। अगर किसान कर्ज माफ करने, फसल के वाजिब दाम व सब्सिडी देने की मांग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, गोलियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने अशोकनगर में शहीद किसानों को श्रद्धांजली देने जा रहे कार्यकर्ताओं पर की गई कार्यवाही की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह से आंदोलनों का दमन करना सरकार का घोर अलोकतांत्रिक कदम है।

अशोकनगर: सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सत्यवान

इंदौर हाईकोर्ट के एडवोकेट व सामाजिक कार्यकर्ता श्री अनिल त्रिवेदी, एआईकेकेएमएस के राज्य सचिव मनीष श्रीवास्तव, एसयूसीआई(सी) प्रदेश कमेटी सदस्य कॉ. प्रदीप आर.बी. और एसयूसीआई(सी) जिला सचिव कॉ. सचिन जैन ने भी सभा को संबोधित किया। अध्यक्षता एसयूसीआई(सी) की प्रदेश कमेटी के सदस्य कॉ. लोकेश शर्मा ने की। पार्टी के म.प्र. के राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल, पार्टी के प्रदेश कमेटी सदस्य कॉ. उमाप्रसाद, कॉ. सुनील गोपाल के अलावा श्री नरेन्द्र भदौरिया, श्री राकेश मिश्रा भी सभा में मौजूद रहे।

अंत में कलेक्टर को प्रतिनिधि मण्डल द्वारा ज्ञापन दिया गया जिसमें आंदोलनरत किसानों की जायज मांगों को पूरा करने एवं अशोकनगर के कार्यकर्ताओं पर लगाये गये मुकदमें वापिस लेने की मांग की गई।

किसान मुक्ति यात्रा शुरू

मध्यप्रदेश : म.प्र. में चल रहे किसान आन्दोलन के दौरान 6 जून को मंदसौर जिले में पुलिस फायरिंग में 6 किसान शहीद हुए थे। इस घटना के एक माह के बाद 6 जुलाई को देश भर के किसान संगठनों द्वारा मिल कर मंदसौर से चम्पारन तक एक किसान मुक्ति यात्रा 6 जुलाई से 2 अक्तूबर तक निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत मंदसौर में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजली देते हुए हुई। इसमें ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से कॉ. हिमांशु श्रीवास्तव ने हिस्सा लिया। दूसरे दिन यात्रा इन्दौर पहुंची जहां ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन के प्रमोद नामदेव व अन्य साथी शामिल हुए और मध्यप्रदेश के अंतिम पड़ाव बड़वानी जिले तक यात्रा में शामिल रहे।

किसान मुक्ति यात्रा में शामिल किसान संगठनों के कार्यकर्ता

कर्जामाफी की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन

रोहतक (हरियाणा) : बीजेपी सरकार की किसान-विरोधी नीति के खिलाफ ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के बैनर तले 27 जून को यहां स्थानीय छोटूराम पार्क में सैकड़ों किसान इकट्ठे हुए और शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। अम्बेडकर चौक पर पहुंच कर म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक कर उन्होंने मंदसौर में आन्दोलनकारी किसानों पर की गई पुलिस फायरिंग के खिलाफ अपना रोष जताया। किसानों ने लघु सचिवालय जाकर उपायुक्त, रोहतक की मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई कि किसानों को सभी फसलों के लाभकारी दाम दिये जाएं और कृषि कर्ज माफ किये जाएं। प्रदर्शन की अगुआई संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. अनूप सिंह मातनहेल, प्रदेश सचिव कॉ. जयकरण माण्डौठी, उपाध्यक्ष कॉ. विजय कुमार व कॉ. बाबूराम ने की।

कॉ. अनूप सिंह ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले वायदा किया था कि सत्ता में आये तो पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक फसलों के लागत खर्ज से 50 प्रतिशत बढ़ा कर लाभकारी दाम देंगे लेकिन सत्ता में आते ही अपने वायदे से मुकर गए।

कॉ. जयकरण ने कहा कि सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के कारण किसान की लगातार दुर्दशा होती जा रही है। खेती में लागत ज्यादा और आमदनी कम होने से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। तीन लाख से ज्यादा किसान देश में आत्महत्या कर चुके हैं। प्रतिदिन 30-35 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार ने बड़े-बड़े सरमायेदारों का 6-7 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है जबकि गरीब किसान-मजदूरों का मामूली सा कर्ज माफ नहीं कर रही है।

कॉ. विजय कुमार और कॉ. बाबूराम ने भी बात रखी।

रोहतक: किसानों की मांगों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए किसान

रोहतक: किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ पुतला फूंकते हुए किसान

कृषि कर्ज माफी...

(पृष्ठ 2 का शेष)

किसानों की दरिद्रता एवं विवशता दूर करने का कोई ठोस उपाय नहीं करती हैं। जब कभी सरकार किसानों के कल्याण की बात करती है तो उसका अभिप्राय शायद ही गरीब व सीमांत किसान, बटाईदार व खेतीहर मजदूर का कल्याण होता है। बल्कि कुछ मुट्ठी भर साधन-सम्पन्न ग्रामीण तबका, धनी किसान, बड़े-बड़े फार्मों के मालिक उनके जेहन में होते हैं। कृषि उत्पाद ऋण या कृषि ऋण देने के मामलों में भी यही बात है। केन्द्र सरकार, वह चाहे जिस किसी भी शासक पूँजीपति वर्ग की पार्टी द्वारा संचालित हो, सत्ता का खेल चलाने के लिए वार्षिक बजट के दौरान सिर्फ ढकोसलापूर्ण घोषणाएं करती है। किसानों की दशा सुधारने के लिए उसमें से कितनी हैं जो कदम उठाने की कोशिश करती हैं? वर्तमान में बीजेपी प्रधानमंत्री ने तो वायदों में एक कदम बढ़कर किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी करने की बात कर डाली है। उनकी पार्टी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि फसल के लागत मूल्य पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ उपज का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। किसानों के साथ-साथ बाकी शोषित गरीब जनता के लिए इस प्रकार के वायदे जो चुनाव के दौरान किए गए हैं उन्हें सुन-सुन कर लोग भूल चुके हैं। वे बखूबी समझ चुकें है कि ये सब चालाकी भरे वायदे तोड़ने के लिए ही किये जाते हैं। ये महज चुनावी जुमले हैं।

प्रत्येक बजट में बड़ी धूम-धाम से घोषणा की जाती है कि कृषि ऋण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है। किन्तु मौजूदा सत्तासीन सरकार सहित कोई भी सरकार आमजन को सूचित करना तो छोड़िए, क्या कभी संसद को रिपोर्ट करती है कि इस बजट की कितनी राशि गरीब किसानों को दी गई है? हम जानते हैं कि वे नहीं कर सकती हैं क्योंकि उधार का बड़ा भाग वितरक तंत्र से मिलिभगत कर धनाढ्यों व सुविधा-सम्पन्नों द्वारा हथिया लिया जाता है। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही गरीब एवं सीमांत किसानों तक पहुँच पाता है। प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट होना चाहिए कि कृषि लोन का मतलब संस्थान (बैंक व वित्तीय संस्थान जिसमें हाल के दिनों में सूक्ष्म वित्तीय आऊटलेट भी सम्मिलित हैं) का क्रेडिट (उधार) नहीं है जो व्यक्तिगत तौर पर किसान मात्र को दिया गया है। संस्थान का क्रेडिट मतलब–कॉरपोरेट किसान, किसानों का सहकारी समूह तथा दूसरे संगठन जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, पशु पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन इत्यादि कृषि आधारित व्यवसायों में भण्डारण केन्द्र, गोदाम, बखार, दुकान, कोल्ड स्टोरेज यूनिट निर्माण तथा मिट्टी संरक्षण व जल संचरण के विकास के लिए, बीज उत्पादन, जैविक कीटनाशक तथा जैव-जनक संवर्धन आदि सभी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ दूसरे सहायक कृषि गतिविधि के लिए भी उधार राशि हैं जैसे–कृषि व्यवसायिक केन्द्र, कृषि उपचार, खाद्य एवं कृषि प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा केन्द्र, जिसमें ट्रैक्टर, बुलडोज़र आदि का जखीरा शामिल है। जो धनाढ्यों द्वारा या संगठनों द्वारा संचालित है। इसलिए जब यह कहा जाता है कि कुल कृषि लोन 10 लाख करोड़ अनुमानित है तब इसका मतलब उपरोक्त तमाम कृषि क्रेडिट से है। ऋण देने की दृष्टि में एक सीमांत किसान का मतलब वह किसान है जिसके पास एक हैक्टेयर भूमि हो तथा लघु किसान वे हैं जिन्हें एक या दो हैक्टेयर कृषि भूमि हो। इन निर्धन किसानों द्वारा काफी बाधाओं को पार करते हुए तमाम प्रक्रिया पूरा कर जो कर्ज की राशि मिलती है वह मात्र 72 हजार रुपये होती है। इसके अलावा बड़े कृषि व्यवसायी सहित उद्योगपतियों को जो कर्जे दिए जाते हैं उस पर 8 प्रतिशत से कम ब्याज लगाया जाता है जबकि किसानों के कर्जे पर 12 से 15 प्रतिशत ब्याज दर होती है। बहुत सारे जरूरतमंदों को बैंकों से अथवा सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से कर्जे नहीं मिल पाने की स्थिति में गरीब व सीमांत किसान, भूमिहीन किसान एवं ग्रामीण दस्तकार स्थानीय साहूकारों से ऊँची ब्याज दर पर कभी-कभी 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर कर्जे लेने के लिए बाध्य होते हैं। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 80 मिलियन (8 करोड़) लघु एवं सीमांत किसान (जिनके पास एक या दो हैक्टेयर कृषि भूमि हो) कर्जों के लिए इन्हीं साहूकारों पर निर्भर हैं। बचे 22.1 मिलियन (2 करोड़ 21 लाख) किसान कर्जे के लिए सूदखोरों व संबंधियों पर आश्रित हैं। यही कारण है कि गरीब किसान कर्जे के जाल में फंस जाते हैं।

किसानों के कर्ज बकायादार होने की वजह

किन्तु क्यों वे कर्ज नहीं चुका सकते हैं? क्या ऐसा है कि वे कर्ज चुका सकते हैं परन्तु नहीं चुकाते हैं? अथवा कुछ वजहें हैं? कुछ तथ्यों पर सरसरी निगाह डालने से पता चल जाता है। खेती करने के लिए किसानों को लागत जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल एवं सिंचाई सुविधा की जरूरत होती है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तथा बड़े कॉरपोरेट को इस क्षेत्र में घुसपैठ का आदेश मिलने के बाद इन सामग्रियों की कीमतें दूसरी वस्तुओं की तरह ही आसमान छू रही हैं। एक विश्लेषण से पता चलता है कि 2004-05 तथा 2014-2015 के बीच मध्यप्रदेश में गेहूँ के लिए प्रति हैक्टेयर खाद व बीज की कीमत दुगुनी हो गई। कोई दूसरा विकल्प न रहने के कारण किसान इन जरूरी सामग्रियों को खुले बाजार से मनमाने दामों पर खरीदने के लिए बाध्य हैं। यहाँ तक कि खेतों में पानी लगाने अर्थात् सिंचाई के लिए मोटर पम्प में जरूरी डीजल व बिजली की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ गई हैं। फिर सिंचाई का सवाल है। यह हैरत की बात है कि आजादी के बाद जनता के पैसों से निर्मित विशाल डैम मानसून के दौरान वर्षा जल को पर्याप्त रूप में संग्रह नहीं कर सकते हैं ताकि सूखे या कम वर्षा की स्थिति में सिंचाई सुविधा प्रदान कर सकें। बल्कि इसके विपरीत ये मानसून के मौसम में या इसके तुरन्त बाद पानी छोड़ते हैं जिसके कारण मानव निर्मित बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इससे फसल को नुकसान होता है और अंततः किसानों का जीवन तबाह हो जाता है। इन सबके साथ बेबस दरिद्र किसान उस समय विवश हो जाता है जब प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, बिन मौसम बारिश तथा आँधी की मार पड़ती हैं जिससे संपूर्ण नहीं तो अच्छी-खासी फसल का नुकसान हो जाता है। जहाँ सत्ताधारी लोग अपने देश की तकनीकी श्रेष्ठता का दम्भ भरते हुए उल्लेख करते हैं कि कैसे शक्तिशाली सैटेलाइट का प्रक्षेपण हुआ या उच्च तकनीक वाली मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, जबकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मुसीबत से खुद निपटने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जंगली जानवरों का हमला, महामारी, खराब बीज के चलते उपज की कमी आदि की समस्या आती है, सो अलग। बेशक, किसानों को राहत, मुआवज़ा व बीमा भुगतान की सरकारी सहायता की जरूरत है। लम्बे समय से लंबित इन मांगों को समझते हुए ही वर्तमान बीजेपी-नीत सरकार ने एक नई स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खूब धूमधाम से प्रायोजित किया। किन्तु कुछ ही समय में यह स्कीम नई बोतल में पुरानी शराब साबित हुई। यह स्कीम दोषपूर्ण चरित्र, जोखिम भरी कार्यविधि, कार्यप्रणाली और तंत्र के अनियंत्रित भ्रष्टाचार से पीड़ित किसान को किसी प्रकार का फायदा न पहुँचा सकी। यह पाया गया कि किसानों को राहत मिलने के बजाए हजारों-करोड़ों जनता का रूपया निजी बीमा कंपनियों को चला गया। केन्द्र व सूबे की सरकार किसी रिवाज की तरह उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। लेकिन वहाँ भी चालाकी भरा अंदाज ही देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर केन्द्रीय सरकार 23 वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है तो नौकरशाहों के लिए यह सिर्फ 2 उपज तक सीमित हो जाती है अर्थात् गेहूँ एवं चावल, वह भी केवल कुछ सूबों में ही। अनुमानित है कि 90 प्रतिशत से अधिक भारतीय किसान एम.एस.पी. मूल्य नहीं ले पाते हैं। अभी केन्द्र ने चारों तरफ सिलसिलेवार जनाक्रोश को देखकर 2017-2018 के फसली वर्ष के लिए दाल, खाद्य तेल तथा रूई के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है तथा सभी प्रदेशों से कहा है कि इसे हर हाल में लागू करें ताकि किसानों को अपनी उपज को कम कीमत में बेचना न पड़े। किन्तु सभी किसान जानते हैं कि सिर्फ घोषणा का कोई अर्थ नहीं है। जब तक भ्रष्ट ग्रामीण दलाल व पंचायत पदाधिकारी, जमाखोर, प्रशासन, बिचौलिया, सत्ताधारी दल क्षत्रप, ग्रामीण अभिजात्य, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जो सरकारी खरीद तंत्र को संचालित करते हैं तथा किसानों को सीधे तौर पर चलाते हैं, के आपसी गठजोड़ को तोड़ने का समवेत ईमानदार प्रयास न किया जाए। यह साँठ-गाँठ बिल्कुल सरकारी तंत्रों की नाक के नीचे हो रही है, अगर मिलिभगत न भी हो तो किसान अपनी उपज को औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं, विभिन्न स्थानों पर जिसे ग्रामीण भाषा में ''गेट'' कहा जाता है वहाँ इस उपज की जमाखोरी होती है और फिर यह थोक व्यापारी को या कोल्ड स्टोरेज मालिक को ऊँची दर पर बेच दी जाती है। अंत में जब उपज से तमाम बिचौलियों द्वारा मोटी रकम चूस ली जाती है, तब यह खुदरा व्यापारी के पास पहुँचती है। यहाँ उपभोक्ता जो भुगतान करता है उसमें एवं किसान को मिले दाम में बड़ा अंतर होता है। विडम्बना है कि जब उपज अच्छी होती है तब दाम गिर जाते हैं। इस प्रकार गठजोड़ से घिरे भ्रष्ट सरकारी खरीद तंत्र के कारनामों से किसानों की आय निम्न से निम्नतर होती जाती है। केन्द्र में या सूबे में बैठी कोई सरकार चाहे जितनी चिल्ल-पौं मचा ले, कोई कोशिश इन परिस्थितियों को सुधारने में काम नहीं करती है क्योंकि इस सारी साँठगाँठ द्वारा ही शासक बुर्जुआ व पेटी बुर्जुआ दलों को चुनाव में सहयोग मिलता है। शोषित व लुटे-पिटे किसान अपनी पीड़ा व त्रासदी से नाउम्मीद होकर खड़े ताकते रह जाते हैं। इसके साथ ही बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार महंगी होती जा रही हैं। अनाज व खाद्य तेल के साथ-साथ दूसरे प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को सब्सिडी के साथ वितरण करने वाली राशन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पूँजीवाद का समस्त शोषण केवल मूल्य वृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर एक क्षेत्र में फैल चुका है। हर दिन, हर क्षण एक खौफनाक मंजर बन गया है। परिणामस्वरूप दरिद्र व बेबस किसान सहित गरीब व वंचित का चेहरा सूख कर जर्द हो गया है। उनकी खरीद शक्ति निम्न से निम्नतर हो चुकी है। हवा का झोंका उसे बेपर्दा कर रहा है। त्रासदीपूर्ण मानव जीवन को सहेजने के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इसी परिदृश्य में किसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है। क्रूर-कपटी, दुष्ट या आरामकुर्सी के समालोचक के अलावा कौन होगा जो इस वास्तविकता से मुँह चुराकर गरीब किसान को इरादतन कर्ज न चुकाने का आक्षेप मंढ़ दे जो जीवन और मौत से जूझ रहा हो।

किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं का खौफनाक मंजर व सड़ियल बुर्जुआ राजनेताओं की अमानवीयता

यह अत्यंत हृदयविदारक है कि लम्बे समय से भुखमरी के शिकार, कर्ज न चुका पाने की हालत में तथा जानलेवा तकलीफ को झेल पाने में असमर्थ किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले दो दशकों के अन्दर 3.5 लाख से ज्यादा किसानों की आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज है। पिछले दो सालों में किसान खुदकुशी की दर में 26 प्रतिशत वृद्धि की रिपोर्ट मिली है। जून 2017 के पहले पखवाड़े में ही 12 किसान मध्यप्रदेश में अपनी इहलीला समाप्त कर चुके हैं। इसी समय पाँच किसान उत्तर प्रदेश में खुदकुशी कर चुके थे। उत्तराखण्ड में भी एक 56 साल के किसान ने कर्ज न चुका पाने की वजह से 16 जून को खुदकुशी कर ली। कोई कल्पना कर सकता है कि भूख की क्या तड़प होती

(शेष पृष्ठ 7 पर)

महिलाओं के ज्वलंत मुद्दों पर महिला सम्मेलन सम्पन्न

भोपाल : महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती रचना अग्रवाल

भोपाल (म.प्र.) : ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) के तत्वावधान में 9 जुलाई को प्रथम भोपाल जिला स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का प्रारंभ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें 'हम भारत की बेटी हैं', 'नारी सोच जरा' और 'कोमल है, कमजोर नहीं तू' जैसे जोशीले गीत प्रस्तुत किए गए और युवतियों द्वारा दहेज के खिलाफ 'मांगपत्र' नाटक नारी का मंचन किया गया। सर्वप्रथम नशाखोरी, अश्लीलता और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ एक प्रस्ताव कुमारी पद्मा द्वारा पढ़ा गया जिस पर श्रीमती रितु श्रीवास्तव ने बात रखी। श्रीमती जॉली सरकार द्वारा उद्घाटन भाषण में सम्मेलन की जरूरत को समझाकर और वर्तमान राजनैतिक-सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला। नशाखोरी, अश्लीलता और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ जोरदार आंदोलन खड़ा करने की अपील की गई ताकि समाज में तेजी से हो रहें नैतिक पतन पर कुछ रोक लगाई जाए और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों व अपराधों में कुछ कमी आ सके।

ऑल इंड़िया एम एस एस की राज्य सचिव श्रीमती रचना अग्रवाल ने अपनी बात में बताया कि पूंजीवाद आज तीव्र संकट की चपेट में है। इसलिए भंयकर मंहगाई, बेरोजगारी होने पर भी सरकार नोटबंदी, जीएसटी, सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण, सरकारी राशन प्रणाली खत्म करने जैसी नीतियों को लागू कर रही है। महिलाएं शराब की दुकान तोड़ने के लिए मजबूर हुई हैं। आंदोलनों से भयभीत मध्यप्रदेश सरकार नशे, अश्लीलता व अवैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देकर इंसान की विचार-विश्लेषण शक्ति और नैतिकता को नष्ट कर उसे पशु के स्तर पर गिरा रही है। इसलिए नन्हीं बच्चियों तक पर भीषण अपराध बढ़ रहे हैं।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ श्रमिक नेता व साहित्यकार श्री जी.एस असिवाल उपस्थित रहे।

संगठन की भोपाल जिला सचिव कुमारी आरती शर्मा ने बताया कि भोपाल में महिलाएं, बच्चियां व छात्राएं आज अपने आपको घोर असुरक्षित महसूस करती हैं। 70 प्रतिशत से भी अधिक बच्चें व महिलाएं कुपोषित हैं अर्थात इनको पेट भर खाना भी नहीं मिल पा रहा है। फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।

भोपाल जिला अध्यक्ष श्रीमती रितु श्रीवास्तव ने जोरदार जनांदोलन गठित करने की महिलाओं से अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेहनतकश वर्ग की पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के भोपाल जिला सचिव कॉ. जे.सी.बरई ने सम्मेलन मे शामिल महिलाओं व बच्चियों का क्रांतिकारी अभिवादन किया। उन्होंने न केवल महिलाओं पर बढ़ते हमलों के खिलाफ बल्कि जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ भी आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। अंत में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही ए.आई.एम.एस.एस. की राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती चंद्रा पात्र द्वारा उद्बोधन किया गया। सरकार से जस्टिस वर्मा कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। कार्यक्रम का संचालन कु. आरती शर्मा ने किया।

संगठन की जिला कमिटी की 13 सदस्सीय कार्यकारिणी गठित की गई व 17 सदस्यीय जिला परिषद् चुनी गई। जिला कमेटी में रितु श्रीवास्तव को अध्यक्ष, फूलवती को उपाध्यक्ष, आरती शर्मा को सचिव, किरण, पद्मा, वर्षा, शर्मिला, भागवती, किस्मती, अरुणा, राधामुनी, सुनीता, पूजा, गीता को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया।

आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रदर्शनों में जाने से रोकने का विरोध

रोहतक (हरियाणा) : एआईयूटीयूसी के प्रदेशाध्यक्ष कॉ. सत्यवान ने 4 जुलाई को जारी एक बयान में रोहतक जिला की पी.ओ. और सीडीपीओ द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की नेत्रियों को धमका कर उनसे नाजायज माफीनामा लिखवाने और यूनियन की गतिविधियों में शामिल होने पर नौकरी से निकालने की धमकियां देने का कड़ा विरोध किया। केन्द्रीय श्रमिक संगठन के नेता ने कहा कि आंगनवाड़ी नेत्रियों को प्रताड़ित करना घोर असंवैधानिक व नाजायत है। उन्होंने बताया कि सोनीपत की चार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बर्खास्तगी के खिलाफ 7 जून से महिला व बाल विकास मंत्री के सोनीपत आवास के सामने यूनियन का धरना लगातार चल रहा है। इस धरने में वे अपनी मांगों को जनतांत्रिक ढंग से उठा रही हैं। आंगनवाड़ी कर्मियों को डरा-धमका कर धरने में शामिल होने से ये अधिकारी रोक रहे हैं। श्रमिक नेता ने कहा कि इसके खिलाफ वे प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर उन्हें इन जनतंत्र-विरोधी हथकण्डों से वाकिफ करा उक्त अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग करेंगे। साथ ही प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कर्मियों के आन्दोलन को तेज किया जाऐगा। प्रदेश की सभी ट्रेड यूनियनें इस पर एकमत हैं और इस अलोकतांत्रिक दमन-उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मोबाइल टावर कामगारों ने किया जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन

नई दिल्ली : बिहार राज्य मोबाइल टावर कामगार यूनियन की ओर से 21-22 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। यूनियन नेताओं ने न्यूनतम मजदूरी 18000 रु. मासिक देने, सभी कर्मियों की सेवा स्थायी करने, सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने, काम के घंटे 8 सुनिश्चित करने, जनवादी अधिकारों पर हमले बंद करने, कामगारों पर किए गए झुठे मुकदमें वापस लेने, अन्य कर्मचारियों की तरह छुट्टियाँ सुनिश्चित करने की मांग की। इसमें बिहार के विभिन्न जिलों से मोबाइल टावरों में कार्यरत गार्डों एवं टेक्निशियनों ने भाग लिया।

एआईयूटीयूसी के राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य कॉ. रमेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आन्दोलन का नेतृत्व और रास्ता सही होना बहुत महत्वपूर्ण है। कामगारों को दोस्त और दुश्मन की समझ होनी चाहिए। कामगारों के पास आज आन्दोलन के सिवा और कोई विकल्प नहीं है।

धरने-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी बिहार राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. मो. इदरीस ने कहा कि हम कामगार साथियों को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। उन्होंने हर जिले में कमिटी निर्माण पर जोर दिया।

धरने-प्रदर्शन का मंच संचालन एआईयूटीयूसी बिहार राज्य कमिटी के सदस्य कॉ. सूर्यकर जितेन्द्र ने किया। मोबाइल टावर के कामगारों को बिहार से आंदोलन की शुरूआत कर जंतर-मंतर तक ले आने के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में मजदूरों को जो भी हक और अधिकार मिले हैं वह आंदोलन से मिले हैं। इसलिए हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए और ताकत बढ़ाने के लिए एकताबद्ध सचेत संघर्ष करने की जरूरत है।

धरने-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी बिहार राज्य कमिटी के सदस्य कॉ. नरेश राम ने कहा कि आंदोलन-विरोधी लोगों से बचाकर रखना अत्यावश्यक है।

इस धरने-प्रदर्शन की अध्यक्षता बिहार राज्य मोबाइल टावर कामगार यूनियन के अध्यक्ष कुमोद कुमार ने की। अन्य वक्ताओं में यूनियन के सचिव अमरेन्द्र कुमार, मिथिलेश कुमार पांडेय, धर्मेन्द्र कुमार, प्रमोद कुमार सिंह आदि शामिल थे। 9 सूत्री मांगों का एक स्मार पत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, श्रम मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय को सौंपा गया।

महान नवम्बर क्रान्ति की 100वीं वर्षगांठ पर बाइक मार्च

रेवाड़ी : बाइक मार्च में शरीक एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता

रेवाड़ी (हरियाणा) : पूंजीवादी व्यवस्था के कारण पनप रही महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज के बोझ, किसानों की आत्महत्याएं, इलाज व शिक्षा के अभाव, महिलाओं पर बढ़ते जुल्म, शराब, नशाखोरी, सांस्कृतिक पतन, जनवादी अधिकारों के हनन, निजीकरण, बढ़ते शोषण, भेदभाव, भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आन्दोलन गठित करने के एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के आह्वान और दुनिया की पहली समाजवादी क्रान्ति की 100वीं वर्षगांठ पर 29 जुलाई को रेवाड़ी में आयोजित होने जा रहे समारोह में शामिल होने की अपील के साथ जिले के 50 से अधिक गांवों, कस्बों में बाइक मार्च किया गया। इसमें सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसे पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य व प्रांतीय सचिव कॉमरेड सत्यवान ने पार्टी के जिला सचिव कॉ. राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में नेहरू पार्क से इस बाइक मार्च को लाल झण्डा थमा कर रवाना किया। इस बाइक मार्च के दौरान गांव-गांव में प्रचार किया गया। और 29 जुलाई को रेवाड़ी के राव तुलाराम पार्क में होने जा रहे समारोह में पधारने की अपील की गई। कोसली में शराब के खिलाफ चल रहे आन्दोलन को भी समर्थन दिया।

इसमें मुख्य रूप से किसान नेता रामकुमार, अमर सिंह, रामफल, करण सिंह, मजदूर नेता बलराम, अमृतलाल आदि शामिल रहे।

स्टडी कैम्प लगाया गया

घाटशिला (झारखण्ड) : महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एसयूसीआई(कम्यनिस्ट) की ओर से 9 जुलाई को यहां एक दिवसीय स्टडी कैम्प लगाया गया। कैम्प का संचालन पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड स्वप्न चटर्जी द्वारा किया गया। विषय था '' समाजवाद में रूस का सर्वांगीण विकास, उसके पतन का कारण और हमारे लिए इसके सबक'' सभा की अध्यक्षता पार्टी के झारखण्ड राज्य सचिव कॉमरेड रबिन समाजपति ने की।

6 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

सर्वहारा दृष्टिकोण

22 जुलाई से 5 अगस्त, 2017

सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से पास–फेल प्रणाली लागू करवाने के लिए

ऑल इण्डिया डीएसओ ने मनाया विरोध दिवस

दिल्ली : पहली कक्ष से पास–फेल चालू करने में साजिशाना देरी के खिलाफ ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. की ऑल इण्डिया कमेटी के आह्वान पर संगठन की दिल्ली कमेटी की ओर 17 जुलाई को विरोध दिवस मनाया गया। इस दिन जंतर मंतर पर एक प्रतिवाद सभा की गई और केन्द्रीय एचआरडी मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। सभा में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया।

प्रतिवाद सभा को एआईडीएसओ के ऑल इण्डिया उपाध्यक्ष कॉ. भास्करानंद, दिल्ली राज्य कमेटी के अध्यक्ष कॉ. प्रशांत कुमार, दिल्ली राज्य सचिव कॉ. श्रेया सिंह और अन्य छात्र नेताओं ने संबोधित किया।

सभा का संचालन एआईडीएसओ के दिल्ली राज्य उपाध्यक्ष कॉ. राहुल सरकार ने किया।

रोहतक (हरियाणा) : 17 जुलाई को छात्र संगठन ऑल इण्डिया डैमोक्रेटिक स्टूडेन्टस ऑर्गेनाइजेशन व युवा संगठन ऑल इण्डिया डैमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूलों में पहली कक्षा से पास–फेल प्रणाली तुरन्त लागू करने में सरकार के षड़यन्त्रकारी विलम्ब के खिलाफ शहर में जुलूस निकाला व मुख्यमंत्री के नाम डी सी, रोहतक की मार्फत ज्ञापन सौंपा।

छात्र–नौजवानों को सम्बोधित करते हुए एआईडीएसओ के हरियाणा प्रदेश सचिव कॉ. हरीश कुमार ने कहा कि 2009 में 'शिक्षा का अधिकार' कानून के तहत 8वीं कक्षा तक पास–फेल प्रणाली खत्म करने से छात्रों का भारी नुकसान हुआ है, जिसने एक पीढ़ी को पूरी तरह से पंगु बना दिया है। बेरोकटोक पास करने की नीति से शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। छात्रों के ड्रापआऊट में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। 'संसदीय स्थाई कमेटी' ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि पांचवी कक्षा के 53.3 फीसदी छात्र दूसरी कक्षा की पुस्तकें तक नहीं पढ़ सकते, 46.6 फीसदी छात्र दो अंकों की सामान्य जोड़–घटा भी नहीं कर सकते। 8वीं कक्षा के अधिकतर छात्र हिन्दी की एक लाइन भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं। परिणामस्वरूप छात्र फेल हो जाते हैं। 'बेरोकटोक पास प्रणाली' लागू होने से 60 प्रतिशत तक प्राइमरी शिक्षा व्यापार की भेंट चढ़ गई है। इससे दोहरी शिक्षा प्रणाली को बढावा मिल रहा है। एक तरफ तो सरकारी स्कूल हैं, जिनमें सिर्फ गरीबों के बच्चे पढते हैं। इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। और दूसरी तरफ हैं प्राइवेट स्कूल, जो अच्छी शिक्षा देने के नाम पर भारी मुनाफा लूट रहे हैं। पार्लियामेन्टरी स्टैण्डिंग कमेटी व अन्य शिक्षा संबन्धी कमेटियों ने 'बेरोकटोक पास प्रणाली' के दुष्परिणाम को स्वीकारते हुए 'पास–फेल प्रणाली' को दोबारा लागू करने के पक्ष में अपना मत दिया था। छात्र, शिक्षक, अभिभावक व शिक्षा प्रेमी लोग भी 'पास–फेल प्रणाली' लागू करने की बार–बार मांग कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा की इतनी भारी बर्बादी के पश्चात भी सरकार द्वारा इस मांग को लागू नहीं करना एक घोर षड़यन्त्र है।

एआईडीवाईओ के हरियाणा प्रदेश सचिव कॉ. बलवान सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा की जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ने व पूंजीपतियों को मुनाफा पहुँचाने के उद्देश्य से निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दे रही है। सरकारी स्कूलों को बन्द कर स्कूली शिक्षा का पूर्णरूप से निजीकरण करने का घोर षड़यन्त्रकारी कदम उठा रही है। इस नीति को 'क्लोजर व मर्जर' नाम दिया गया है। इस नीति के नाम पर सरकार कोई नया स्कूल खोलने की बजाय उल्टे सरकारी स्कूलों को बन्द कर रही है। इससे सरकारी स्कूलों में मिलने वाली नौकरियां भी समाप्त हो जाएंगी। बेरोकटोक पास नीति से सरकार अनपढ़ बेरोजगारों की फौज खड़ा करना चाहती है जो अपने हक की मांग न कर सकें।

छात्र संगठन एआईडीएसओ 2009 से ही इस बेरोकटोक पास नीति के खिलाफ आन्दोलन करता आ रहा है। आन्दोलन के दबाव में विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं व पश्चिम बंगाल में छात्र आंदोलन की जीत हुई है व वहां की सरकार ने पास–फेल प्रणाली को इसी सत्र से लागू करने की घोषणा की है। जब तक खट्टर सरकार संगठन की इस मांग को नहीं मानती तब तक संगठन आंदोलन करता रहेगा। संगठन ने ज्ञापन में मांग की कि स्कूलों में पास–फेल प्रणाली पहली कक्षा से तुरन्त लागू की जाए, 5वीं व 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा बहाल की जाए, शिक्षकों के खाली पड़े पद भरे जाएं, पर्याप्त संख्या में शिक्षक व अन्य स्टाफ भर्ती किया जाए, सभी सरकारी स्कूलों में बिजली, पानी, भवन व शौचालयों समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं का उचित प्रबंध किया जाए। संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि इन मांगों को तुरन्त पूरा किया जाए, नहीं तो ओर भी जोरदार आन्दोलन किया जाएगा और इन मुद्दों पर छात्रों व बुद्धिजीवियों समेत शिक्षकों व अभिभावकों को भी लामबन्द किया जाएगा।

वक्ताओं में छात्र नेता उमेश कुमार रोहतक, हिम्मत सिंह हिसार, जसवन्त सिंह रेवाड़ी, अमित सोनीपत तथा युवा नेता अजय रेवाड़ी, वजीर सिंह गुड़गांव, सतीस नारनौल, नरेश कैथल व संदीप मेहरा भिवानी ने भी बात रखी।

देवास (म.प्र.) : कक्षा 1 से पास–फेल प्रणाली लागू करने में सरकार की साजिशाना देरी के खिलाफ देशव्यापी विरोध दिवस के तहत आल इंडिया डीएसओ की देवास जिला इकाई द्वारा स्थानीय नावल्टी चोराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र जुलूस के रूप में नावल्टी चौराहे से कलेक्ट्रेट तक गए। वहां मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए डीएसओ के जिला संयोजक राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने 2009 में आर.टी.ई. के तहत कक्षा 8 तक पास–फेल प्रणाली यह तर्क देकर ख़त्म की थी कि इससे ड्रापआउट की संख्या में कमी आएगी लेकिन इसके दुष्परिणाम स्वरूप ड्रॉपआउट की संख्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि ज्ञान को बर्बाद करने वाली सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ भी छात्र संगठन आल इंडिया डीएसओ द्वारा 8 वर्षो तक आंदोलन चलाया गया और बाद में जीत भी हुई। हमको इस आंदोलन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने सभी से कक्षा 1 से पास–फेल लागू कराने के लिए आंदोलन चलाने की अपील की। नंबर 1 स्कूल के ऑल इण्डिया डीएसओ के अध्यक्ष विनोद प्रजापति ने भी बात रखी। प्रदर्शन का संचालन जिला संयोजन समिति के सदस्य सुनील सिंह डोडिया ने किया।

आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का राजनीतिक शिक्षण शिविर सम्पन्न

अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) : 7 से 9 जुलाई तक यहां एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य सांगठनिक कमेटी की ओर से एक राज्य स्तरीय राजनीतिक शिक्षण शिविर लगाया गया। इस साल महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष पर साल भर चलने वाले समारोह के सिलसिले में यह शिविर आयोजित किया गया। कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गान के साथ शिक्षण शिविर शुरू हुआ। पार्टी की आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य सांगठनिक कमेटी के राज्य सचिव कॉमरेड के. श्रीधर ने अपने उद्घाटन भाषण में राजनीतिक शिक्षण शिविर के महत्व पर रोशनी डाली जो कि सभी साथियों का वैचारिक–सांस्कृतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए आयोजित किया जाता है।

पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड के. राधाकृष्ण ने पहले दिन ऐतिहासिक नवम्बर क्रान्ति, इसे करने के पीछे जो चिंतन और व्यवहार था, महान लेनिन द्वारा साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्ति के जमाने में मार्क्सवादी विज्ञान के सही इस्तेमाल, बोल्शेविक पार्टी के निर्माण, दक्षिणपंथी और वामपंथी भटकावों के खिलाफ उनके संघर्ष, समाजवाद का निर्माण करने में स्तालिन की भूमिका, संशोधनवाद के विनाशकारी प्रभाव जो उनकी मृत्यु के बाद वहां जोर पकड़ गये आदि विषयों पर चर्चा की। दूसरे दिन उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी संगठन के लेनिनीय नीति–सिद्धांतों जैसे कि जनवादी केन्द्रीयता के सिद्धांत पर विस्तार से बात रखी। कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा जिस तरह सामूहिक नेतृत्व की धारणा व सामूहिक कार्यपद्धति की विस्तार से व्याख्या की गई है, उसके बारे में उन्होंने बताया। तीसरे दिन उन्होंने राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर चर्चा की और फासीवाद के बढ़ते रुझान का मुकाबला करने के लिए जनवादी जन आन्दोलन गठित करने पर बल दिया। उन्होंने मार्क्सवाद–लेनिनवाद– शिवदास घोष चिन्तनधारा में महारत हासिल करने के लिए सभी साथियों का आह्वान किया जो हमारी मुक्ति लाने और साथ ही साथ समाज का क्रान्तिकारी बदलाव लाने की एकमात्र उम्मीद हो सकती है।

कुल 110 साथियों ने इस शिविर में शिरकत की। वे 9 जिलों से थे, तेलंगाना राज्य से हैदराबाद व जहीराबाद, आंध्र प्रदेश से अनंतपुर, वाईजाग, गंटूर, कुरनूल, चित्तूर, नेलौर व श्रीकाकुलम। हर सत्र के बाद शिक्षण शिविर में आये साथियों को 6 ग्रुपों में बांट कर राज्य सांगठनिक कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा तेलगू में अनुवाद करके सब समझाया गया। साथियों ने इसमें बड़े उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। उनके द्वारा उठाये गए सभी सवालों का जवाब कॉमरेड राधाकृष्ण द्वारा गहराई से दिया गया। गूंजायमान नारों और अन्तर्राष्ट्रीय गान गायन के साथ शिक्षण शिविर का समापन हुआ।

जीएसटी का विरोध

आरोन (म.प्र.) : 1 जुलाई से लागू नई कर प्रणाली जीएसटी और इसकी विसंगतियों को लेकर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) कार्यकर्ताओं ने स्थानीय श्रीदास हनुमान चौराहे पर जीएसटी के खिलाफ जोर शोर से नारे लगाकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों को पार्टी के स्थानीय प्रभारी कॉमरेड मनीष श्रीवास्तव ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी बड़ी–बड़ी कम्पनियों के इशारों पर लाया गया काला कानून है। इसमें जनबूझ कर हर महीने तीन रिटर्न भरने का प्रावधान किया गया है जिससे लाखों छोटे दुकानदारों के लिए एक बहुत बड़ा झमेला है और वे तबाह हो जायेंगे। इससे बड़े–बड़े शॉपिंग मालों के लिए रास्ता साफ हो जायेगा।

विरोध सभा का संचालन कॉ. महेन्द्र नायक ने किया।

कृषि कर्ज माफी...

(पृष्ठ 4 का शेष)

है, भूख से बिलबिलाते परिवार के अन्य सदस्यों को देखना कितना असहनीय पीड़ा का सबब बन जाता है कि एक आदमी अपने जीवन को समाप्त करने का त्रासदीपूर्ण कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। क्या कोई इस तरह के आत्मघाती कदम उस समय नहीं उठाता है जब स्थिति को संभालने के सारे दरवाजे बन्द हो जाते हैं?

परन्तु धोखेबाज, चालबाज, भ्रष्ट बुर्जुआ नेता व मंत्री एवं उसके चाटुकार इस कदर पतित हो गए हैं कि इन दुखद आत्महत्याओं के लिए नशाखोरी, पारिवारिक कलह, बिमारी, ड्रग्स, दहेज, प्रेमसंबंध, नपुंसकता आदि को जिम्मेदार बताने में भी गुरेज नहीं करते हैं। कोई भी समझ सकता है कि सच को दबाने की खातिर एवं पूँजीवादी शोषण-शासन की हृदयहीन सेवा में वे किस स्तर तक नीचे गिर गए हैं।

कर्जमाफी की मांग का औचित्य

उपर्युक्त चर्चा से किसी भी सचेत इन्सान को आभास हो सकता है कि आर्थिक कंगाली, बेबसी एवं घोर दरिद्रता किसानों को कर्ज डिफाल्टर बना रही है। और अगर ऐसा है तो किसानों द्वारा कर्ज माफी की मांग क्या जायज नहीं है? इन मुकुट के हीरे-जवाहरात जराग्रस्त बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों से यक्ष प्रश्न है कि जब सरकार एन.पी.ए.– नॉन पर्फोमिंग एसेट – गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ या डूबे हुए कर्ज के लाखों करोड़ों रुपये माफ करती है या औद्योगिक घरानों, बड़े व्यापारियों तथा एकाधिकारी पूँजीपतियों को दस वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये की टैक्स रियायत देती है, तब इससे देश की अर्थनीति को क्या सकारात्मक लाभ पहुँचता है? ऐसा क्यों होता है कि आर.बी.आई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकारी बैंक के लोन डिफाल्टरों की लिस्ट को सार्वजनिक नहीं करती है। वह यह बहाना बनाती है कि इससे देश के आर्थिक हित को नुकसान पहुँचेगा। क्यों केन्द्रीय सरकार लगभग 3 ट्रीलियन बकाया रुपयों की वसूली नहीं कर रही है जो उसने विशाल दूरसंचार कम्पनी को स्पैक्ट्रम खरीद के लिए उधार दिये थे, जिसे उसने पहले ही खरीद लिया था। क्या यह साबित नहीं करता है कि ''राष्ट्र के आर्थिक हित'' का मतलब जनता के फण्ड की ठगी करने वाले मुट्ठी भर अमीरों का, जनता के पैसों की चोरी करने वालों का अथवा स्वेच्छिक डिफाल्टरों का हित है? फिर जब किसानों की कर्ज माफी का सवाल आता है, तब आर्थिक बोझ की मार पड़ने लगती है। है न अद्‌भुत सच!

यही वजह है कि जो अर्थशास्त्री-समीक्षकगण किसानों के लोन डिफाल्टर होने को जानबूझकर मुआवजा बतौर माफी लेने की कहानी करार देते हैं वे या तो पूरी तरह से वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं या फिर जानबूझकर ऐसा बताने का ढोंग करते हैं। किसानों की कृषि ऋण माफी की मांग जिन्दा रहने की ताकीद है। वे प्रोत्साहन ढिलाई या रियायत पाने वाले उम्मीदवार नहीं हैं। पूँजीवादी भारत में ये उपचार अति धनवान, बड़े कारपोरेट व कृषि व्यवसायिओं को मिलता है। वे शासक वर्ग या उसके पालतू जो दूसरे को धोखा देने के लिए साजिश रचते रहते हैं, दूसरे की मेहनत पर आनन्द भोगते हैं, झूठ और फरेब में डूबे रहते हैं तथा वास्तविकता को झुठलाने का नया स्वांग रचते हैं, की तरह चालबाज नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि किसान इस व्यवस्था को धोखा नहीं दे रहे हैं, यह व्यवस्था उन्हें धोखा दे रही है।

सीमित एवं सशर्त है कर्जमाफी

जनता के आन्दोलन के दबाव में केन्द्र तथा विभिन्न सूबों की सरकारें दोनों हाल में कृषि ऋण माफी की घोषणा कर रही हैं। अभी ऐसा लगता है कि विभिन्न सूबाई सरकारों के बीच कृषि ऋण माफ करने के मामलों में उदारता दिखाने की प्रतिस्पर्द्धा चल पड़ा है कि कौन ज्यादा किसानों का हमदर्द है। किन्तु वस्तुस्थिति को थोड़ी सी गहराई से देखने पर स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह माफी की घोषणा में कितनी मक्कारी व धोखा छिपा हुआ है। सबसे पहले औसतन एक तिहाई भारतीय लघु एवं सीमांत किसान ऋण के लिए सरकारी संस्थानों में जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अनुमानतः 8 राज्यों में कर्ज माफी की मांग करने वाले 32.8 मिलियन लघु एवं सीमांत किसानों में से 10.6 मिलियन किसान ही कर्जमाफी के योग्य हैं। साथ ही सभी माफी सशर्त हैं। माफी की राशि सुनिश्चित है तथा वह कृषि ऋण की कौन सी प्रकार है उसकी भी योग्यता है। इससे भी अधिक भ्रष्ट बैंक अधिकारियों का एक समूह, निर्लज्ज अभिकर्त्ताओं एवं बिचौलियों के साथ साँठगाँठ कर किसानों से जरूरी राशि समायोचित कर औपचारिक वसूली किए बिना ही स्वतः उनका नया कृषि लोन खड़ा कर देते हैं। भ्रष्ट माध्यम द्वारा पिछले वर्ष लिए गए ऋण जो दूसरे वर्ष के दायरे में नहीं आएगा। इसमें भी आडम्बर इतना है, पेचीदगियाँ इतनी हैं, अगर राहत दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत किसान ही इसका लाभ उठा पाते हैं। इसके अतिरिक्त कर्जमाफी को लागू करने में टालमटोल की स्थिति बनाई जाती है सो अलग। फसल बोन-रोपने का मौसम सर पर होता है। इस तरह किसान नहीं जानते हैं कि उनका पुराना लोन माफ हो जाएगा और अगर हो जाएगा तो कब और कैसे आने वाले मौसम में उन्हें खेती में काम आने वाली जरूरी चीजें (इनपुट्स) खरीदने के लिए फण्ड मुहैया होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो हर प्रकार से संभावित लाभ के रास्ते को रोकने की तमाम कोशिश की जाती हैं।

किसानों को लोन डिफाल्टर बना रही है संकटग्रस्त पूँजीवादी व्यवस्था

यह याद रखना होगा कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का संकट कुछ सतही कारकों जैस कर्जमाफी के कारण नहीं है। यह इसी व्यवस्था में विद्यमान है। बढ़ते हुए इस अंदरूनी संकट का निवारण न होने के चलते ही पूँजीवाद अपनी कब्र खुद खोद रहा है। कोई रास्ता नहीं बचा है जो पूँजीवाद को इस संकट से निजात दिला सके वह चाहे नीम-हकीम उपचार हो या पीड़ा हटाने वाला कोई टोटका या औषधि हो। मौजूदा मरणासन्न, संकटग्रस्त पूँजीवाद है जो बेरोजगारी एवं छंटनी पैदा कर रहा है, महंगाई बढ़ा रहा है, गरीबी व भुखमरी बढ़ा रहा है तथा तमाम भ्रष्टाचार, निकृष्ट संस्कृति, अमानवीय व असुरक्षा का वातावरण फैला रहा है। दूसरे, तमाम शोषित जनमानस की तरह किसान भी पूँजीवादी व्यवस्था के शोषण के शिकार हो रहे हैं। यह व्यवस्था कुछ मुट्ठी भर पूँजीवादी शासकों तथा उसके चाटुकारों का खजाना भर रही है। जबकि दूसरी तरफ समस्त गरीब, निर्धन, वंचित श्रमिक जन के रास्ते में पहाड़ सी बाधा उत्पन्न करते हुए उसे जीर्ण-शीर्ण करने पर आमादा है। यह पूँजीवादी व्यवस्था ही किसानों को लोन-डिफाल्टर बना रही है। इसलिए किसानों के पास जर्जर इस प्रतिक्रियावादी व्यवस्था को क्रान्ति द्वारा उखाड़ फेंकने के सिवा और कोई चारा नहीं है। जब तक यह कार्य संपन्न नहीं होता है तब तक कर्ज माफी एवं वैतनिक मांग को हासिल करने का संघर्ष 100 प्रतिशत न्यायिक है। पूँजीवाद के बोझ को झेलने के लिए शोषित-पीड़ित जन को विवश क्यों होना चाहिए? पूँजीवादी संकट के मार को ढोने के लिए अभावग्रस्त किसान को बाध्य क्यों होना चाहिए? इसलिए पूँजीवादी शासक वर्ग तथा उनके जरखरीद ताबेदारों द्वारा लिए गए घातक कदम के खिलाफ उनका संघर्ष उचित व सराहनीय है।

किसानों का कर्त्तव्य

कर्जमाफी एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल पर समूचे देश में किसान आन्दोलन के नये उभार ने एक नई स्थिति पैदा कर दी है जो शक्तिशाली संगठित, सचेतन किसान संघर्ष के उत्कर्ष का परिपूरक है। किसानों की मदद की जानी चाहिए ताकि वे निराशा, हताशा एवं आत्मघात की छाया से बाहर निकल सकें तथा खुदकुशी का रास्ता चुनने के बजाय वे अपनी फौरी मांगों के लिए संघर्ष का रास्ता अपना सकें। समस्त प्रगतिशील किसान संगठन को एक होना चाहिए ताकि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत आन्दोलन को जोरदार करते हुए दीर्घकालिक जारी रख सके एक दृढ़ संकल्प लें कि आगे कोई कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या के लिए विवश न होगा। आन्दोलन में हमारी मांग केवल जो नहीं मिला है उसके लिए ही नहीं होना चाहिए बल्कि हमारी मांग इसके लिए भी होनी चाहिए जिसे हम सरकार को दबाव में लाकर हासिल किए हैं किन्तु वह अपर्याप्त है और उसमें तत्परता की कमी है। प्रत्येक विचारशील, बड़े हृदयवान लोग जो किसान के इन सवालों के साथ हमदर्दी रखते हैं उन्हें आगे आना चाहिए और जिस तरह से भी हो आन्दोलन को मजबूत करने के लिए मदद देनी चाहिए। संघर्ष के रास्ते में किसान स्वयं साहस व दृढ़ता हासिल करेंगे, हर प्रकार के हमलों का जवाब देंगे, हर प्रकार के विपरीत परिस्थितियों एवं अस्थाई बाधा का मुकाबला करते हुए दीर्घकालिक अमिट संघर्ष के जज्बात को विकसित करेंगे। तथा संघर्ष को सही दिशा में संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि नेतृत्वकारी बुर्जुआ या पेटी बुर्जुआ दलों से समझौता न करें। नेतृत्व का सवाल सबसे महत्त्वपूर्ण है। संघर्षशील किसानों को क्रान्तिकारी नेतृत्व की पहचान होनी चाहिए जो समझौता नहीं करते हैं या फिर संकुचित चुनावी फायदों के लिए पीठ में चाकू नहीं घोंपते हैं, आन्दोलन को बीच में नहीं छोड़ते हैं या फिर पैसे या सत्ता की खातिर अपने को नहीं बेचते हैं। एस.यू.सी.आई.(सी) तथा इसका किसान फ्रण्ट ए.आई.के.के.एम.एस. किसानों के फौरी संघर्ष के साथ खड़ा होने के लिए, आन्दोलन की एकता बनाए रख कर संघर्ष को दीर्घकालिक बनाने के लिए तथा उनको राजनीतिक चेतना से लैस करते हुए उनके इन संघर्षों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

अपहृत लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ़ कर इन्साफ दिलाने की लगाई गुहार

जयपुर (राजस्थान) : ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) के तत्वावधान में 9 जुलाई को खो-नागोरियान(जयपुर) एसएचओ को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें जल्द से जल्द न्याय दिलाये जाने की मांग की गई। लुनियावास निवासी एक असहाय लड़की कथित तौर पर डेढ़ महीने पहले 23 मई को अपहृत हुई थी। लेकिन 24 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

संगठन ने ज्ञापन सौंप कर मांग की कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाये और लड़की को ढूंढ़ कर उसके परिजनों को न्याय दिलाया जाये। ज्ञापन देने वालों में ममता, नीरू, चमेली व धीरू सिंह शामिल थी।

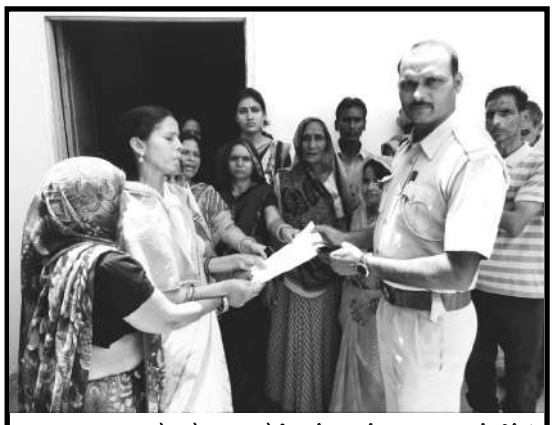

जयपुर : एसएचओ को ज्ञापन देती हुई एआईएमएसएस कार्यकर्त्रियां

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Publication : July 20, 2017

सर्वहारा दृष्टिकोण

22 जुलाई से 5 अगस्त, 2017

हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-इस्राइल समझौतों की एसयूसीआई(सी) ने की कड़ी निंदा

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 7 जुलाई को जारी एक बयान में कहा :

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस्राइल के प्रधानमंत्री बैंजामिन नितिनयाहु के साथ जनदीकियां बढ़ाने और फिलस्तीन को नजरअंदाज किये जाने की एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) कड़ी निंदा करती है। हाल ही की अपनी यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने इस्राइल सरकार से कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं जिनमें तकनीक के नवीनीकरण, आतंकवाद का मुकाबला करने इत्यादि में आपसी सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। दुनिया भर के जनवाद पसन्द लोग इस्राइली प्रशासन से घोर नफरत करते हैं क्योंकि इसने फिलस्तीनियों पर अमानवीय और क्रूर हमले किये, इसने फिलस्तीनियों की जमीन जबरन और गैर कानूनी ढंग से हड़प ली और यह अनेक अन्य अरब देशों के प्रति हमलावर रवैया रखता है। इस घृणित हमलावर इस्राइल के साथ भारत का सामरिक सहयोग भारतीय जनता की साम्राज्यवाद-विरोधी परम्परा के खिलाफ है। आजादी के बाद से ही भारत सरकार फिलस्तीनियों के हित की हिमायती रही है और कम से कम जबानी तौर पर ही सही इस्राइल की हमलावर और विस्तारवादी नीति का हमेशा विरोध किया। लेकिन हाल के वर्षों में इस नीति को पलट देने का और भी पर्दाफाश हो गया है। भारत ने वस्तुतः फिलस्तीनी हितों को तिलांजलि दे दी है और रक्षा मामलों में और साथ-साथ शस्त्रों की खरीद में इस्राइल के साथ भारत सहयोग कर रहा है। तकनीकी के नवीनीकरण के नाम पर हुआ हालिया समझौता अत्याधुनिक हथियारों के उत्पादन के लिए है। असल में भारत क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभरने के अपने प्रयास में अमेरिका और मध्यपूर्व में इसकी मिलिट्री चौकी इस्राइल के साथ सांठगांठ कर रहा है। नरेन्द्र मोदी सरकार के बेशर्म साम्राज्यवादी स्टैण्ड के खिलाफ एसूयसीआई(कम्युनिस्ट) प्रतिवाद करती है। एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) यह मांग करती है कि यह अपना इस्राइल-परस्त स्टैण्ड तुरंत छोड़े और फिलस्तीन के जायज हितों को अपना बिना शर्त समर्थन प्रदान करे।

केन्द्र सरकार द्वारा पुड्डुचेरी विधानसभा के लिए नितांत गैरजनवादी ढंग से बीजेपी-संघ परिवार के तीन कार्यकर्ताओं के विधायक मनोनीत करने की एसयूसीआई(सी) ने की कड़ी निंदा

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 5 जुलाई को जारी एक बयान में कहा :

केन्द्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी की राज्य विधानसभा के लिए उप-राज्यपाल की सिफारिश पर 3 विधायकों को अचानक नामांकित किये जाने के बारे में भारत सरकार के गृह मंत्रलय की एकतरफा और चौंकाने वाली घोषणा की एसयूसीआई(सी) कड़ी निंदा करती है। पुड्डुचेरी के लोगों और उनके चुनावी अधिकारों पर थोप दिये जाने वाला यह बेहूदा, बेलगाम और गैर-जनवादी नुकसानदेह अन्यायपूर्ण कृत्य है।

लोगों द्वारा निर्वाचित होकर सत्ता में आई सरकार के उचित न्यायसंगत प्रस्ताव व सिफारिश के बिना ही यह घोषणा और मनोनयन उपराज्यपाल के साथ मिलिभगत से काम कर रही बीजेपी-नीत केन्द्र सरकार के छुपे मन्सूबे को बहुत कुछ बयां कर देती है। पुड्डुचेरी की उप-राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के बाद से ही किरण बेदी पर राज्य में सत्तासीन सरकार से ठन जाने और टकराव पैदा करने के आरोप लगते रहे हैं। इसका बुरा असर आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ रहा है क्योंकि चुनी हुई राज्य सरकार के कामकाज के मामले में मनोनीत उप-राज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप के स्वेच्छाचारी कृत्यों की वजह से बहुत सी रोजमर्रा की गतिविधियां ठप्प हो गई हैं।

फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने और भारत के साथ अपने विलय के बाद से ही पुड्डुचेरी के लोगों द्वारा एक भी बीजेपी का प्रतिनिधि कभी चुना नहीं गया है जिन्होंने राज्य विधानसभा में उनके प्रवेश को निरंतर रोका है, जैसा कि अब तक तमाम चुनावों में इसके उम्मीदवारों के निराशाजनक प्रदर्शन से इसकी पुष्टि होती है।

इस पृष्ठभूमि में बीजेपी के अध्यक्ष, संयोगवश जो गत विधानसभा चुनावों में एक हारा हुआ उम्मीदवार था, बीजेपी के राज्य खजांची और हिन्दुत्व ब्रिगेड के एक अन्य आदमी जो एक निजी स्कूल चलाता है, इनको विधानसभा में नामांकित करना लोगों की चाहत और अधिकार, दोनों का ही भावना और अभ्यास में मजाक उड़ाना है।

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) विधायकों के रूप में इन व्यक्तियों का नामांकन वापस लेने की मांग करती है और राष्ट्रपति के हस्तक्षेप का आग्रह करती है ताकि केन्द्र सरकार की इस नाजायज दखलअंदाजी और चुनी हुई सरकार के अधिकारों पर किये गये प्रहार को दुरस्त किया जा सके। एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) राज्य के लोगों के साथ-साथ न केवल पुड्डुचेरी के सही सोच रखने वाले जनवाद पसंद नागरिका से बल्कि देश भर के लोगों से भी अपील करती है कि सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी-नीत केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर उठाये जा रहे ऐसे नितांत अलोकतांत्रिक व स्वेच्छाचारी कदमों के खिलाफ वे एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें।

जनविरोधी जीएसटी के खिलाफ जुलूस व नुक्कड़ सभा

शालीमार बाग, दिल्ली

दिल्ली : सरकार की जनविरोधी नीति जीएसटी के खिलाफ एसयूसीआई (सी) की शालीमार बाग लोकल कमेटी की ओर से 8 जुलाई को जुलूस व नुक्कड़ सभा की गई। इस कार्यक्रम में लोकल व्यापारियों व दुकानदारों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया तथा इस विरोध प्रदर्शन का भरपूर समर्थन किया। सभा को शालीमार बाग सेल की इंचार्ज कॉ. नीतू खन्ना, लोकल व्यापारी श्री त्रिलोक तथा लोकल कमेटी इंचार्ज कॉ. प्रकाश देवी ने सम्बोधित किया।

सरकार की जनविरोधी नीति का विरोध करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी अर्थात् वस्तु एवं सेवा कर से जनता पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ जाएगा और इससे महंगाई ओर भी बढ़ जाएगी। सरकार की यह नीति बड़ी पूंजी के हक में छोटी पूंजी को बर्बाद करने वाली है। सरकार की इस नीति के खिलाफ देशभर में जोरदार विरोध आंदोलन हो रहे हैं। उन्होंने आम जनता, मजदूरों व व्यापारियों से अपील की कि विरोध आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करें ताकि इसे वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके।

सभा के बाद जूलूस निकाला गया जिसमें कार्यकर्ताओं ने 'जीएसटी पर रोक लगाओं', 'केन्द्र सरकार होश में आओ', 'जीएसटी वापस लो', 'जनविरोधी नीति के खिलाफ जनआंदोलन तेज करो' के नारे लगाते हुए जनता से अपील की। कार्यक्रम का संचालन कॉ. नीतू खन्ना ने किया।

महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष पर जनसभा

कुरूक्षेत्र (हरियाणा) : महान नवम्बर क्रान्ति की 100वीं वर्षगांठ पर सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर स्थानीय जाट धर्मशाला के हाल में 12 जुलाई को जनसभा की गई। सभा की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव कॉ. रोशनलाल ने की। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य एवं प्रांतीय सचिव कॉमरेड सत्यवान थे। उन्होंने बताया कि आज से 100 साल पहले नवम्बर 1917 में रूस देश में महान क्रान्ति हुई थी। उन्होंने कहा कि महान लेनिन के नेतृत्व में वहां के किसान-मजदूरों ने पूंजीपतियों का राज उखाड़ फेंका था और शोषणमुक्त समाजवादी व्यवस्था कायम की थी। इससे प्रभावित होकर कई देशों के महापुरुषों ने समाजवाद को अपनाया था और इसकी तहेदिल से प्रशंसा की थी। पार्टी राज्य कमेटी के सदस्य कॉ. बाबूराम ने कहा कि नवम्बर 1917 की क्रान्ति के शताब्दी वर्ष में क्रान्ति से जुड़ी बातों को लोगों में प्रचारित किया जायेगा ताकि लोगों को समाजवाद के बारे में पता चल सके।

सभा में कॉ. राजकुमार, कॉ. रामसरूप, कॉ. नंदलाल आदि भी मौजूद थे।

कुरूक्षेत्र

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com

फोन नं. : 011-25726631, 9868350503